

through this satellite and how this Global Communication System will affect our present system?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri J. K. Gujral): (a) The question of foreign aid for India's Satellite Communication Ground Station is still under consideration.

(b) The overseas traffic is at present handled mostly on high frequency radio system, which is insufficient to provide reliable and prompt telephone service and is also incapable of meeting the growing demands, due to congestion in HF Spectrum.

(c) The present indications are that about 20 countries, including India, are expected to operate with the Indian Ocean Satellite as soon as they are technically equipped to do so. The existing system will continue to be used for communication with countries which will not have switched over to Satellite working, and any equipment becoming surplus will be diverted for other internal requirements.

**Chief Development Commissioner,
Andamans**

*1106. Shri K. R. Ganesh: Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to appoint a Chief Development Commissioner in the Andaman and Nicobar Islands equivalent in status to the Chief Commissioner;

(b) if so, whether Government have considered the desirability of this post in the context of the financial stringency;

(c) the specific duties, to be performed by the proposed Chief Development Commissioner; and

(d) whether these duties could not be undertaken by the Islands Development Commissioner?

The Minister of State in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) It is proposed to create a post of Chief Development-cum-Rehabilitation Commissioner for the execution of the accelerated development programme in the Andaman and Nicobar Islands. The officer appointed to the post will be lower in status than the Chief Commissioner and will work under him.

(b) Yes, Sir.

(c) The Chief Development-cum-Rehabilitation Commissioner will be responsible for preparing the Project Reports and the execution of various projects under the accelerated development programme of the Islands. He will also be in over all charge of all developmental work in the Islands.

(d) The Island's Development Commissioner is, comparatively speaking, a junior officer. The Chief Commissioner has indicated that, for the carrying out of these duties, there should be a Chief Development-cum-Rehabilitation Commissioner in addition to the Development Commissioner

राजभाषा विधेयक

* 1107. श्री बसन्त सिंह कुशावह :
श्री प्रकाशचौर शास्त्री :
श्री आत्स दास :
डा० सुब्रं प्रकाश पुरी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करने कि :

(क) क्या देश की कुछ धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक संस्थाओं ने सतत् में पुर-स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित राजभाषा विधेयक का विरोध किया है;

(ख) उनमें से प्रमुख संस्थाओं तथा व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उन संस्थाओं ने इसके बारे में कुछ सुझाव भी दिये हैं; और

(ब) यदि हां, तो उनका ध्यौरा क्या है औ उनके बारे में सरकार की क्या प्रति-धिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या अरण कुमल) : (क) इस विषय में कुछ संस्थाओं से अध्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । [पुरतकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT 994/67]

(ग) जी हां ।

हिन्दी में उत्तर

- *1108. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री महााराज सिंह भारती :
श्री निहाल सिंह :
श्री शिव पुजन शास्त्री :
श्री प्रकाशशरिर शास्त्री :
श्री रामाचतार शर्मा :
श्री भालू दास :
श्री हुकम चन्ध कश्वाय :
श्री रघुशर सिंह शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुसवाहू :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह भवौरिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा प्रायोग के सोलहवें प्रतिवेदन में यह लिखा गया है कि एक उम्मीदवार को जिसने अपने उत्तर हिन्दी में लिखे थे उन प्रश्न-पत्रों में शुन्यांक दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस कार्यवाही को उचित ठहराया है ;

(ग) यदि हां, तो संविधान का इस प्रकार उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या संघ लोक सेवा प्रायोग की परीक्षा के लिये सरकार का विचार अंग्रेजी के वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी को रखने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव बन्हलू) : (क) से (ग) सदन के समा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । [पुरतकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT—995/67]

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने प्रायोग द्वारा ली जाने वाली सभी प्रथिल भारतीय तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी के साथ संविधान की प्राटवी अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में लागू करने का विचार किया है । यह कार्य परीक्षाओं की योजना प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं तथा इस परिवर्तन को लागू करने के समय प्रादि के सम्बन्ध में प्रायोग की सलाह प्राप्त होने के बाद किया जाएगा ।

अन्वमान द्वीप समूह में वेतन-क्रम तथा सेवा की शर्तें

- *1109. डा० सुबं प्रकाश पुरी :
श्री भालू दास :
श्री प्रकाशशरिर शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुसवाहू :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या अन्वमान द्वीप समूह में विभिन्न पदों के वेतन-क्रम तथा सेवा-शर्तें मुख्य भूमि में समतुल्य पदों के बतन-क्रमों तथा सेवा की शर्तों से भिन्न हैं ;

(ख) क्या ये द्वीप समूह संघ लोक सेवा प्रायोग के क्षेत्राधिकार में आते हैं ; और